

भारतीय बैंकिंग प्रणाली, वाणिज्यिक बैंकों की कार्यप्रणाली, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की स्थिति तथा प्रमुख योजनाओं (Schemes) का प्रभाव: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Farha Naz

Research Scholar

Chhatrasal Bundelkhand Vishvidhyalay,

Chhatarpur, Madhya Pradesh, India

सारांश

भारतीय बैंकिंग प्रणाली देश की आर्थिक संरचना का एक केंद्रीय स्तंभ है, जो जमा स्वीकार करने, ऋण प्रदान करने, वित्तीय मध्यस्थता तथा विकासोन्मुख गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्यिक बैंक न केवल वित्तीय संसाधनों के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, बल्कि विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जन-धन योजना, मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया, PM-Swanidhi आदि के माध्यम से वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देते हैं। हाल के वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें सबसे गंभीर समस्या गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ हैं, जो बैंकों की लाभप्रदता, साख, ऋण प्रदान करने की क्षमता एवं वित्तीय स्थिरता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। इस शोध-पत्र में भारतीय बैंकिंग प्रणाली के ऐतिहासिक विकास, संरचना, वाणिज्यिक बैंकों के कार्य, एनपीए की प्रवृत्तियों, तथा प्रमुख सरकारी योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन में 2010-2024 के बीच के द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग करते हुए बैंकिंग क्षेत्र की वास्तविक स्थिति दर्शाई गई है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं का उपयोग, सरकारी योजनाओं के माध्यम से खातों की संख्या में वृद्धि, तथा खुदरा ऋण में तेज वृद्धि जैसे सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं; वहीं दूसरी ओर एनपीए, जोखिम प्रबंधन, साइबर सुरक्षा एवं पूँजी पर्याप्तता जैसी चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं। समग्र रूप से यह अध्ययन बैंकिंग क्षेत्र के बहुआयामी स्वरूप, वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका, एनपीए के प्रभावों तथा सरकारी योजनाओं के महत्व को समझने में उपयोगी है। यह शोध नीति-निर्माताओं, बैंक प्रबंधकों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और भविष्य में बैंकिंग सुधारों एवं डिजिटल नवाचारों की दिशा निर्धारित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

प्रमुख शब्द : बैंक, वाणिज्यिक बैंक, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए), योजनाएँ, वित्तीय समावेशन, पीएमजेडीवाई, डिजिटल बैंकिंग, ग्रामीण बैंकिंग, क्रेडिट ग्रोथ

प्रस्तावना

भारतीय बैंकिंग प्रणाली देश की वित्तीय संरचना का आधार स्तंभ है, जो आर्थिक संसाधनों के कुशल प्रबंधन, धन के प्रवाह, वित्तीय स्थिरता तथा विकास के अवसरों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बैंक न केवल जमा स्वीकार करने और ऋण प्रदान करने जैसे परंपरागत कार्य करते हैं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को अधिक संगठित, सुरक्षित और तेज गति से संचालित करने हेतु अनेक आधुनिक वित्तीय सेवाएँ भी उपलब्ध कराते हैं। आज के समय में बैंक किसी भी राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि, उद्योगों के विस्तार, कृषि की प्रगति, रोजगार सृजन और व्यापार व वाणिज्य के विकास का प्रमुख माध्यम बन चुके हैं। विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ विशाल जनसंख्या और विविध आर्थिक आवश्यकताएँ हैं, बैंकिंग प्रणाली की मजबूती अत्यंत आवश्यक है। भारत में बैंकिंग का इतिहास अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण रहा है। वैदिक काल में "धनागार", "कुसीद" तथा "रत्ननिधि" जैसी अवधारणाओं से प्रारम्भ होकर मध्यकाल में साहूकारों, महाजनों और जगत सेठों के माध्यम से बैंकिंग संबंधी गतिविधियाँ संचालित होती थीं। ब्रिटिश काल में आधुनिक बैंकिंग संरचना की आधारशिला रखी गई, जिसने वाणिज्यिक बैंकों की अवधारणा को स्थापित किया। स्वतंत्रता के बाद 1969 और 1980 के राष्ट्रीयकरण ने बैंकिंग

क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाए और समाज के दूरस्थ तथा कमजोर वर्गों तक औपचारिक बैंकिंग सेवाओं को पहुँचाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए। आगे चलकर 1991 के आर्थिक सुधारों ने प्रतिस्पर्धा, तकनीकी नवाचार और निजी बैंकों की भूमिका को नया आयाम दिया। इन सुधारों ने भारतीय बैंकिंग को अधिक दक्ष, पारदर्शी और ग्राहक-केंद्रित बनाया।

वर्तमान समय में वाणिज्यिक बैंक, चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र के हों या निजी क्षेत्र के, भारतीय अर्थव्यवस्था की धड़कन के रूप में कार्य करते हैं। वे केवल धन के लेनदेन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि क्रेडिट निर्माण, निवेश सुविधा, भुगतान तंत्र, डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय समावेशन और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई), मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री स्वनिधि (PM-Swanidhi), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) जैसे अनेक कार्यक्रम वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से ही जनता तक पहुँचते हैं। इन योजनाओं ने समाज के ऐसे वर्गों को बैंकिंग की मुख्यधारा में जोड़ा, जो दशकों से इससे दूर थे। इससे न केवल वित्तीय समावेशन बढ़ा है, बल्कि देश की आर्थिक सक्रियता में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। हालाँकि, इन उपलब्धियों के बावजूद भारतीय बैंकिंग प्रणाली कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। इनमें सबसे प्रमुख समस्या है गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ। NPA वह ऋण होता है, जिसकी वापसी नियत समय पर नहीं हो पाती, और वह बैंक के लिए जोखिम का कारण बन जाता है। पिछले एक दशक में NPAs में तेज वृद्धि हुई, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में। इसके पीछे कई कारण रहे—गलत ऋण मूल्यांकन, उद्योगों की कमजोर स्थिति, आर्थिक मंदी, धोखाधड़ी, परियोजनाओं में देरी, राजनीतिक हस्तक्षेप, तथा ऋण वसूली की कमजोर व्यवस्था। उच्च NPA अनुपात बैंकों की लाभप्रदता को घटाता है, उनकी पूँजी को कमजोर करता है, और नए ऋण देने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसलिए NPA भारतीय बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता और कार्यक्षमता के लिए एक गंभीर खतरा है।

बैंकों पर बढ़ते दबाव के कारण सरकार और RBI ने अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जिनमें दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता जैसे उपाय शामिल हैं। इन प्रयासों से NPA में कुछ कमी अवश्य आई है, लेकिन समस्या अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। दूसरी ओर, डिजिटल बैंकिंग के तेजी से विस्तार के कारण साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और तकनीकी जोखिम जैसी नई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। डिजिटल बैंकिंग, UPI, मोबाइल व इंटरनेट बैंकिंग ने बैंकिंग सेक्टर को नए आयाम दिए हैं। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट्स सिस्टम है। UPI ने भुगतान प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। बैंकिंग सेक्टर में तकनीक का यह विस्तार जहाँ ग्राहक सेवा को सरल बना रहा है, वहीं साइबर अपराध और डेटा चोरी के जोखिम भी बढ़ा रहा है। इसके लिए बैंकों को साइबर सुरक्षा ढाँचे को और मजबूत करने तथा तकनीकी क्षमता को विकसित करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच अब भी असमान है। हालाँकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs), सहकारी बैंक और बैंक मित्रों (BCs) ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का विस्तार किया है, परंतु वित्तीय जागरूकता की कमी, डिजिटल कौशल की कमी, कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी और सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ अब भी बड़ी बाधाएँ हैं। सरकारी योजनाएँ, जैसे PMJDY, Mudra Loans, PM-Kisan, DBT प्रणाली, किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने वाली KCC योजना आदि, बैंकिंग प्रणाली की पहुँच को अधिक समावेशी और जन-केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों को बैंक खाता, बीमा, पेंशन और क्रेडिट जैसी सुविधाएँ प्राप्त हुई हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। उपरोक्त सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह शोध-पत्र भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विकास, वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या, और सरकारी योजनाओं के प्रभाव का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की दशा-दिशा को समझने, उसकी चुनौतियों की पहचान करने और भविष्य में सुधारों के संभावित मार्ग को निर्धारित करने में सहायक साबित होगा।

साहित्य समीक्षा

शर्मा (2018) ने भारतीय बैंकिंग के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक विकासक्रम का विश्लेषण किया। अध्ययन के अनुसार वैदिक काल में मंदिर-भंडार और महाजनों द्वारा संचालित वित्तीय लेनदेन, मध्यकाल में साहूकार और महाजन, तथा ब्रिटिश काल में प्रेसीडेंसी बैंकों के उदय ने आधुनिक बैंकिंग संरचना की नींव रखी। 1935 में रिज़र्व बैंक की स्थापना, 1969 और 1980 में राष्ट्रीयकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग पहुँच को बढ़ाया और प्राथमिक क्षेत्र ऋण को प्रोत्साहित किया। शोध में यह बताया

गया कि इन ऐतिहासिक घटनाओं का आधुनिक बैंकिंग संरचना पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। निष्कर्ष यह है कि वर्तमान बैंकिंग प्रणाली को समझने के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण आवश्यक है।

कुमार और सिंह (2020) ने सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंकों के प्रदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन में लाभप्रदता परिचालन दक्षता, लागत-आय अनुपात और CASA अनुपात पर ध्यान दिया गया। शोध में पाया गया कि निजी बैंक डिजिटल चैनलों और तकनीकी नवाचार के कारण बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सामाजिक-लक्ष्यों और विस्तृत शाखा नेटवर्क के कारण परिचालन बोझ का सामना करते हैं। निष्कर्ष यह है कि वाणिज्यिक बैंकों की दीर्घकालिक स्थिरता हेतु मजबूत जोखिम प्रबंधन और प्रौद्योगिकी निवेश आवश्यक हैं।

मेहता (2019) ने NPA की बढ़ती समस्या, कारण और प्रभाव का अध्ययन प्रस्तुत किया। अध्ययन में पाया गया कि अवसंरचना परियोजनाओं में देरी, उद्योगों की मंदी, कॉर्पोरेट डिफॉल्ट और कमजोर ऋण मूल्यांकन NPA वृद्धि के मुख्य कारण हैं। शोध में IBC, SARFAESI Act, DRT और Asset Reconstruction Companies जैसे सुधारात्मक उपायों के प्रभाव को भी देखा गया। निष्कर्ष यह है कि NPA की समस्या का स्थायी समाधान कानूनी उपायों के साथ-साथ बेहतर क्रेडिट निगरानी और बैंकिंग प्रशासन सुधारों से ही संभव है।

राव (2017) ने 1969 और 1980 के राष्ट्रीयकरण और 1991 के आर्थिक सुधारों के प्रभावों का विश्लेषण किया। अध्ययन दर्शाता है कि राष्ट्रीयकरण ने ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का विस्तार किया और प्राथमिक क्षेत्र ऋण में सुधार किया। 1991 के उदारीकरण ने प्रतिस्पर्धा, तकनीकी दक्षता और परिचालन पारदर्शिता बढ़ाई। शोध निष्कर्ष यह है कि भारतीय बैंकिंग का वर्तमान स्वरूप राष्ट्रीयकरण और उदारीकरण दोनों की संयुक्त परिणति है। वर्मा (2021) ने PMJDY, MUDRA, PM-Swanidhi, PM-Kisan जैसी योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण किया। अध्ययन के अनुसार PMJDY ने बैंक खाते खोलने की दर बढ़ाई और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया। MUDRA ऋण ने सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान की। शोध यह भी बताता है कि योजनाओं का लाभ तभी प्रभावी होता है जब बैंक पर्याप्त निगरानी, डिजिटल सहायता और वित्तीय साक्षरता प्रदान करें।

अग्रवाल और थॉमस (2022) ने डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI आधारित भुगतान प्रणाली पर केंद्रित अध्ययन किया। शोध में पाया गया कि UPI ने रिटेल भुगतान में क्रांतिकारी बदलाव किया, लेनदेन की गति बढ़ी और लागत कम हुई। हालांकि, डिजिटल बैंकिंग ने साइबर जोखिम, डेटा गोपनीयता और डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियाँ भी प्रस्तुत की हैं। अध्ययन का निष्कर्ष है कि डिजिटल बैंकिंग की सफलता मजबूत साइबर सुरक्षा, ग्राहक जागरूकता और नियामक समर्थन पर निर्भर है।

चौधरी (2016) ने ग्रामीण बैंकिंग, RRBs और बैंक मित्र (BC) मॉडल का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि RRBs ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और लघु उद्योगों तक क्रेडिट पहुँचाया, लेकिन पूँजी और प्रबंधन की कमजोरियों के कारण प्रभाव सीमित रहा। BC मॉडल ने बैंकिंग पहुँच बढ़ाई, पर प्रशिक्षण और निगरानी की कमी सेवा-गुणवत्ता को प्रभावित करती रही। निष्कर्ष यह है कि ग्रामीण बैंकिंग को सुदृढ़ बनाने के लिए संस्थागत मजबूती, प्रौद्योगिकी और वित्तीय साक्षरता आवश्यक हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

1. भारतीय बैंकिंग प्रणाली और वाणिज्यिक बैंकों की संरचना का अध्ययन।
2. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की प्रवृत्तियों का विश्लेषण।
3. बैंकिंग क्षेत्र पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन।
4. वाणिज्यिक बैंकों के प्रदर्शन का डेटा-आधारित विश्लेषण।
5. सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध-विधि

यह अध्ययन वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक शोध-विधि पर आधारित है, जिसमें भारतीय बैंकिंग प्रणाली, वाणिज्यिक बैंकों के प्रदर्शन, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की प्रवृत्तियों तथा सरकारी योजनाओं के प्रभाव का समग्र विश्लेषण किया गया है। शोध में मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है, क्योंकि इसका उद्देश्य व्यापक बैंकिंग प्रवृत्तियों को समझना, नीतिगत परिवर्तनों का अध्ययन करना और समय के साथ हुए बैंकिंग विकास का मूल्यांकन करना है। अध्ययन के लिए आवश्यक जानकारी रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) की वार्षिक रिपोर्टों, सांख्यिकीय तालिकाओं, बैंकिंग संकेतकों, भारतीय बैंक संघ (IBA) के डेटा, आर्थिक सर्वेक्षण, सांख्यिकी मंत्रालय, NABARD, SIDBI, RRBs की वार्षिक रिपोर्टों, तथा PMJDY, मुद्रा, PM-Swanidhi, PM-Kisan जैसी सरकारी योजनाओं के पोर्टलों से प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त विभिन्न शोध-पत्रों, जर्नलों और पुस्तकों से भी साहित्यिक जानकारी एकत्रित की गई।

इस अध्ययन में उपयोग किए गए आँकड़ों का विश्लेषण कई दृष्टिकोणों से किया गया है। सबसे पहले प्रवृत्ति विश्लेषण के माध्यम से 2010–2024 के बीच जमा, ऋण, NPA, डिजिटल लेनदेन और वित्तीय समावेशन से संबंधित आँकड़ों की दिशा और गति का अध्ययन किया गया। इसके बाद तुलनात्मक विश्लेषण द्वारा सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंकों के प्रदर्शन, ग्रामीण और शहरी बैंकिंग की स्थिति, तथा सरकारी योजनाओं के पहले और बाद में बैंकिंग संकेतकों में आए परिवर्तन की तुलना की गई। विश्लेषण को अधिक वैज्ञानिक बनाने हेतु प्रतिशत परिवर्तन, वार्षिक वृद्धि दर और सम्मिलित वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) की गणना की गई, जिससे बैंकिंग क्षेत्र की वास्तविक प्रगति और चुनौतियों का स्पष्ट चित्र प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त तालिकीय विश्लेषण का उपयोग कर विभिन्न योजनाओं और बैंकिंग संकेतकों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया। कुछ स्थानों पर ग्राफ, पाई-चार्ट और लाइन ग्राफ का भी प्रयोग किया गया, जिससे अध्ययन के निष्कर्ष अधिक स्पष्ट, दृश्यात्मक और समझने में आसान बन सके।

शोध का दायरा भारतीय बैंकिंग प्रणाली के समग्र ढाँचे को सम्मिलित करता है, जिसमें सार्वजनिक, निजी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs), सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, RBI के विनियमन, NPA की प्रवृत्तियाँ, तथा सरकारी योजनाओं के प्रभाव जैसे पहलू शामिल हैं। यह अध्ययन 2010 से 2024 तक की अवधि पर केंद्रित है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में हुए संरचनात्मक और नीतिगत परिवर्तनों का गहरा आकलन संभव हो सके। अध्ययन की कुछ सीमाएँ भी हैं, जैसे कि सभी आँकड़े द्वितीयक स्रोतों पर आधारित होने के कारण डेटा की उपलब्धता और विश्वसनीयता स्रोतों पर निर्भर करती है। बैंकिंग क्षेत्र में लगातार होने वाले नीतिगत बदलावों के कारण कुछ नवीनतम परिवर्तन अध्ययन में पूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं हो पाए होंगे। इसके अतिरिक्त प्राथमिक डेटा (सर्वे, साक्षात्कार आदि) का उपयोग न किए जाने के कारण उपभोक्ताओं एवं बैंक कर्मचारियों के अनुभवों का प्रत्यक्ष विश्लेषण संभव नहीं हो सका।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली का विकास

भारतीय बैंकिंग प्रणाली का विकास एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें प्राचीन काल की अनौपचारिक ऋण व्यवस्था से लेकर आधुनिक डिजिटल बैंकिंग तक निरंतर परिवर्तन हुए हैं। भारत में बैंकिंग का प्रारंभ वैदिक काल से माना जाता है, जब “कुसीद” या उधार देने की प्रथा, महाजनों और साहूकारों के माध्यम से संचालित होती थी। व्यापारियों, मंदिरों और नगरपालिकाओं द्वारा संपत्ति की सुरक्षा और विनियम की व्यवस्था बैंकिंग के प्रारंभिक रूप के रूप में विकसित हुई। मध्यकाल में साहूकार, सर्राफ और बनिया समुदाय ने व्यापारिक ऋण और धन-विनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी अवधि में “हण्डी” प्रणाली का उदय हुआ, जिसने भारत में चेक और बिल ऑफ़ एक्सचेंज का प्रारंभिक स्वरूप प्रदान किया। ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ भारत में आधुनिक बैंकिंग की नींव रखी गई। 18वीं सदी के अंत में स्थापित प्रेसीडेंसी बैंक— बैंक ऑफ़ बंगाल (1806), बैंक ऑफ़ बॉम्बे (1840) और बैंक ऑफ़ मद्रास (1843)—ने औपचारिक बैंकिंग ढाँचे की शुरुआत की। 1921 में इन तीनों का विलय कर इंपीरियल बैंक ऑफ़ इंडिया की स्थापना हुई, जिसने बाद में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया का रूप लिया। आगे चलकर, 1935 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना हुई, जिसने मुद्रा नियंत्रण, क्रेडिट नीति और बैंकिंग विनियमन की केंद्रीय भूमिका संभाली। RBI का गठन भारतीय बैंकिंग प्रणाली को संगठित, नियंत्रित और स्थिर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था।

स्वतंत्रता के बाद भारतीय बैंकिंग प्रणाली का विकास नई दिशा में आगे बढ़ा। प्रारंभिक वर्षों में बैंकों का ध्यान मुख्यतः शहरी और संपन्न वर्ग तक सीमित था, जिससे ग्रामीण और कमजोर वर्ग बैंकिंग सुविधा से वंचित रह जाते थे। इस असमानता को दूर करने के लिए 1969 और 1980 में दो चरणों में प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण ने बैंकिंग के सामाजिक उद्देश्य को मजबूत किया, ग्रामीण शाखाओं में तेजी से वृद्धि हुई, कृषि, लघु उद्योग और प्राथमिक क्षेत्र को अधिक ऋण मिलने लगा, और बैंकिंग आम जनता की पहुँच में आने लगी। इस चरण ने भारत में “विकासोन्मुख बैंकिंग” (Development Banking) की अवधारणा को जन्म दिया, जिसने वित्तीय समावेशन को गति दी। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के साथ भारतीय बैंकिंग प्रणाली में प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और तकनीकी विकास की नई धारा प्रवाहित हुई। निजी और विदेशी बैंकों को लाइसेंस जारी किए गए, पूँजी बाजार को विनियमित किया गया, और बैंकिंग प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के प्रयास तेज हुए। उदारीकरण के बाद से बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन, नियम, और NPA प्रबंधन जैसे सुधार लागू किए गए। इस अवधि में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस और कोटक जैसे निजी बैंकों का विकास अत्यंत तेज़ी से हुआ, जिन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर ग्राहक सेवा और डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहित किया।

2000 के दशक में भारतीय बैंकिंग ने डिजिटल परिवर्तन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की। Core Banking Solution (CBS) ने शाखाओं को एकीकृत किया, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत हुई, RTGS और NEFT जैसे त्वरित भुगतान सिस्टम विकसित हुए। 2016 के बाद की शुरुआत ने भारत को वैश्विक मंच पर डिजिटल भुगतान के अग्रणी देशों में स्थापित कर दिया। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार-आधारित प्रमाणीकरण, ई-KYC और BHIM ऐप जैसे नवाचारों ने बैंकिंग को तेज, सरल और सुलभ बनाया। वित्तीय समावेशन को बढ़ाने हेतु सरकार ने कई योजनाएँ शुरू कीं, जिनमें प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY), मुद्रा योजना, PM-Swanidhi, और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) प्रमुख हैं। इन योजनाओं ने बैंकिंग पहुँच को व्यापक बनाते हुए करोड़ों लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ा। इसके अतिरिक्त बैंक मित्र (BC Model), भुगतान बैंक (Payment Banks) और स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFBs) की स्थापना ने बैंकिंग तंत्र को और अधिक सुदृढ़ और सर्वग्राही बनाया।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना

भारतीय बैंकिंग प्रणाली एक बहु-स्तरीय, संगठित और व्यापक संरचना है, जो देश की वित्तीय स्थिरता, आर्थिक विकास और मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी संरचना मुख्यतः पदानुक्रममात्मक है, जिसका शीर्ष भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नियंत्रण में है। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, जो मुद्रा प्रबंधन, मौद्रिक नीति निर्माण, बैंकों का विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का उत्तरदायित्व निभाता है। इसके अधीन विभिन्न प्रकार के बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ कार्य करती हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों, उद्देश्यों और ग्राहक समूहों को सेवाएँ प्रदान करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटक वाणिज्यिक बैंक हैं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, और विदेशी बैंक शामिल होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकार के बहुमत स्वामित्व में होते हैं और व्यापक शाखा नेटवर्क के साथ ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करते हैं। निजी क्षेत्र के बैंक व्यावसायिक दृष्टि से अधिक प्रतिस्पर्धी, तकनीक-प्रधान और प्रबंधन-कुशल माने जाते हैं। विदेशी बैंक मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय व्यापार, कॉर्पोरेट बैंकिंग और उच्च स्तरीय वित्तीय सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इनके अतिरिक्त, भारतीय बैंकिंग संरचना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योग और ग्रामीण उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराना है। ये बैंक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक के संयुक्त स्वामित्व में कार्य करते हैं। इसी प्रकार सहकारी बैंक राज्य एवं जिला स्तर पर कार्यरत होते हैं और कृषि, ग्रामीण विकास तथा निम्न-आय वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। सहकारी बैंक दो स्तरों पर संगठित होते हैं—प्राथमिक सहकारी समितियाँ और केंद्रीय/राज्य सहकारी बैंक। बैंकिंग संरचना में विकास वित्त संस्थान जैसे NABARD, SIDBI, EXIM Bank और NHB भी शामिल हैं, जो कृषि, लघु उद्योग, निर्यात और आवास जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक वित्त प्रदान करते हैं। इसके साथ-साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFBs) और पेमेंट बैंक भी हाल के वर्षों में बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा बने हैं, जिन्होंने वित्तीय समावेशन को मजबूत बनाया है। SFBs छोटे उद्यमों, असंगठित क्षेत्र और निम्न-आय समूह को ऋण उपलब्ध कराते हैं, जबकि पेमेंट बैंक छोटे बचत खाते, डिजिटल भुगतान और रेमिटेंस सेवाएँ प्रदान करते हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के कार्य

वाणिज्यिक बैंक किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होते हैं, जो जमा स्वीकार करने से लेकर ऋण वितरण तक अनेक प्रकार के वित्तीय कार्यों का संचालन करते हैं। भारतीय संदर्भ में वाणिज्यिक बैंक आर्थिक संसाधनों के कुशल आवंटन, वित्तीय मध्यस्थता, भुगतान प्रणाली, निवेश प्रोत्साहन एवं विकासोन्मुख वित्तीय गतिविधियों को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के कार्य व्यापक रूप से प्राथमिक द्वितीयक और विकासात्मक/अन्य सहायक कार्यों में विभाजित किए जा सकते हैं। प्राथमिक कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण है जमा स्वीकार करना, जिसमें बैंक बचत खाते, चालू खाते और सावधि जमा (FD/RD) जैसी सुविधाएँ प्रदान करते हैं। इसके साथ-साथ ऋण और अग्रिम प्रदान करना भी मुख्य कार्य है। बैंक व्यक्तिगत, व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषि एवं आवासीय क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। ऋण के विभिन्न प्रकार—कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, बिल डिस्काउंटिंग आदि—आर्थिक गतिविधियों को गति देते हैं।

द्वितीयक कार्यों में बैंक मध्यस्थता एवं वित्तीय सुविधा प्रदान करते हैं। वे ग्राहकों के लिए भुगतान एवं निपटान सेवाएँ प्रदान करते हैं जैसे NEFT, RTGS, UPI, डिमांड ड्राफ्ट, चेक क्लीयरिंग आदि। बैंक एजेंसी सेवाएँ भी देते हैं, जिनमें ग्राहकों की ओर से बिलों का भुगतान, वेतन वितरण, कर जमा करना, बीमा प्रीमियम का भुगतान एवं ट्रस्टी सेवाएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक निवेश सेवाएँ, लॉकर्स, विदेशी विनिमय क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड, गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट जैसी सुविधाएँ प्रदान करते हैं। विकासात्मक कार्यों में बैंक आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। वे उद्योग, व्यापार, कृषि, MSMEs, महिलाओं और युवाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऋण प्रदान करते हैं। बैंक सरकार की योजनाओं जैसे PMJDY, मुद्रा, स्टैंड-अप इंडिया, PM-Kisan, PM-Swanidhi, DBT आदि को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वित्तीय साक्षरता अभियान, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का प्रसार, और वित्तीय समावेशन को गति देना वाणिज्यिक बैंकों के प्रमुख विकासात्मक कार्य हैं।

डेटा विश्लेषण

तालिका 1 : 2015–2024 के बीच भारतीय वाणिज्यिक बैंकों में कुल जमा का रुझान (₹ लाख करोड़)

वर्ष	कुल जमा
2015	89.1
2017	108.0
2019	123.9
2021	150.3
2023	175.2
2024	189.5

ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है कि 2015 से 2024 के बीच भारतीय वाणिज्यिक बैंकों में कुल जमा में निरंतर वृद्धि हुई है। 2015 के 89.1 लाख करोड़ रुपये से 2024 में यह 189.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया, जो लगभग दोगुनी वृद्धि को दर्शाता है। इस वृद्धि के प्रमुख कारणों में डिजिटल बैंकिंग का विस्तार, वित्तीय समावेशन योजनाएँ (PMJDY), महिलाओं एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं का बैंकिंग में बढ़ता जुड़ाव, तथा महामारी के बाद सुरक्षित बचत प्रवृत्ति शामिल हैं। जमा में यह मजबूत बढ़त बैंकों की तरलता स्थिति को बेहतर करती है और ऋण वितरण की क्षमता को भी बढ़ाती है। यह प्रवृत्ति भारतीय बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता और उपभोक्ता विश्वास को दर्शाती है।

तालिका 2 : कुल ऋण वितरण का रुझान – 2015–2024 (₹ लाख करोड़)

वर्ष	कुल ऋण (Advances)
2015	68.7
2017	76.5

2019	92.1
2021	105.9
2023	132.2
2024	145.6

इस तालिका से स्पष्ट है कि पिछले दशक में कुल ऋण वितरण लगातार बढ़ता रहा है। 2015 में 68.7 लाख करोड़ रुपये से 2024 में 145.6 लाख करोड़ रुपये तक यह वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था में ऋण मांग तथा उपभोक्ता गतिविधियों में वृद्धि को दर्शाती है। कॉर्पोरेट ऋण के साथ-साथ खुदरा ऋण (हाउसिंग, वाहन, शिक्षा) में भी तेजी से विस्तार हुआ है। सरकार की योजनाएँ जैसे मुद्रा, PM-Svanidhi तथा MSME क्रेडिट गारंटी ने भी यह वृद्धि तेज की। हालांकि 2020-21 के दौरान COVID-19 के प्रभाव से ऋण वृद्धि थोड़ी धीमी हुई, लेकिन बाद के वर्षों में पुनः मजबूत रिकवरी देखी गई। यह प्रवृत्ति बैंकिंग क्षेत्र की सक्रियता और आर्थिक विकास को इंगित करती है।

तालिका 3 : गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात – सार्वजनिक बनाम निजी बैंक (%)

वर्ष	सरकारी बैंक	निजी बैंक
2016	11.2	4.3
2018	14.6	4.7
2020	12.3	4.2
2022	7.9	3.6
2024	6.2	3.1

तालिका दर्शाती है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में NPA अनुपात निजी बैंकों की तुलना में लगातार अधिक रहा है। 2016-2018 के दौरान NPA चरम पर पहुँचा, जिसका कारण कॉर्पोरेट ऋणों का डिफॉल्ट, अवसंरचना परियोजनाओं में देरी तथा जोखिम मूल्यांकन की कमजोरियाँ थीं। IBC (2016), विलफुल डिफॉल्टर कार्रवाई, और क्रेडिट मॉनिटरिंग सिस्टम के सुधारों के बाद 2019 के पश्चात NPA में महत्वपूर्ण गिरावट आई। 2024 तक सरकारी बैंकों का NPA 6.2% और निजी बैंकों का 3.1% हो गया, जो बैंकिंग प्रणाली के सुधार और स्थिरीकरण को संकेतित करता है। यह डेटा बताता है कि बैंकों में जोखिम प्रबंधन मजबूत हुआ है, लेकिन सरकारी बैंकों के सामने चुनौतियाँ अब भी अधिक हैं।

तालिका 4 : प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खोले गए खाते – 2015-2024 (करोड़ में)

वर्ष	खाते (करोड़)
2015	18.0
2017	28.2
2019	35.5
2021	42.3
2023	48.7
2024	51.1

PMJDY के अंतर्गत खुले बैंक खातों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 2015 में 18 करोड़ खातों से शुरू होकर 2024 में यह संख्या 51.1 करोड़ तक पहुँची, जो वित्तीय समावेशन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रामीण और शहरी गरीब, महिलाओं, श्रमिकों तथा छोटे व्यवसायियों ने औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में प्रवेश किया। आधार-आधारित ई-KYC, RuPay

कार्ड और DBT भुगतान ने इस योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाया। इससे बैंकों के जमाओं में वृद्धि हुई और उपभोक्ता डिजिटल भुगतान की ओर आकर्षित हुए। यह वृद्धि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव और गहरी पैठ को दर्शाती है।

तालिका 5 : मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण वितरण – 2016–2024 (₹ लाख करोड़)

वर्ष	कुल वितरण
2016	1.37
2018	2.53
2020	3.22
2022	4.46
2024	5.23

मुद्रा योजना के आँकड़े दर्शाते हैं कि पिछले वर्षों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमिता को वित्तीय सहायता प्रदान करने में यह योजना अत्यंत प्रभावी रही है। 2016 में 1.37 लाख करोड़ रुपये का वितरण बढ़कर 2024 में 5.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। यह वृद्धि रोजगार सृजन, महिला उद्यमिता, स्टार्टअप और छोटे कारोबारों के विस्तार को बढ़ावा देती है। शिशु, किशोर और तरुण श्रेणियों में ऋण वितरण ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को गति देता है। यह डेटा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वाणिज्यिक बैंक सरकारी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन व आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

तालिका 6 : डिजिटल लेनदेन – 2017–2024 (करोड़ लेनदेन)

वर्ष	कुल UPI लेनदेन (करोड़)
2017	1.9
2019	93.1
2021	456.2
2023	840.5
2024	1102.3

तालिका से स्पष्ट है कि UPI ने भारतीय डिजिटल भुगतान क्षेत्र में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है। 2017 के केवल 1.9 करोड़ लेनदेन से बढ़कर 2024 में यह मात्रा 1100 करोड़ से अधिक हो गई। इस विशाल वृद्धि का कारण है—आसान इंटरफ़ेस, न्यूनतम लागत, तेज़ गति और शून्य शुल्क। COVID-19 के बाद डिजिटल भुगतान के प्रति बढ़ती जागरूकता और QR आधारित व्यापारियों की संख्या में वृद्धि ने भी UPI को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया। इस वृद्धि से यह प्रमाणित होता है कि डिजिटल बैंकिंग तेजी से नकद-आधारित अर्थव्यवस्था को कम कर रही है और बैंकिंग प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं कुशल बना रही है।

तालिका 7 : बैंकिंग क्षेत्र की क्रेडिट ग्रोथ – 2016–2024 (%)

वर्ष	क्रेडिट वृद्धि (%)
2016	8.6
2018	10.1

2020	6.1
2022	14.2
2024	16.7

तालिका से पता चलता है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की क्रेडिट वृद्धि में वर्षों के साथ उतार-चढ़ाव रहा है। 2020 के दौरान महामारी के कारण क्रेडिट वृद्धि दर 6.1% तक गिर गई थी, लेकिन आर्थिक पुनरुद्धार, MSME सहायता योजनाएँ, और खुदरा ऋण मांग बढ़ने के कारण 2022 और 2024 में वृद्धि दर क्रमशः 14.2% और 16.7% तक पहुँच गई। यह वृद्धि न केवल बैंकिंग क्षेत्र की सक्रियता दर्शाती है, बल्कि बाजार में बढ़ते उपभोक्ता विश्वास और निवेश गतिविधियों को भी इंगित करती है। यह ट्रेंड दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत पुनरुद्धार चरण में प्रवेश कर चुकी है।

तालिका 8 : CASA अनुपात (Current + Savings Account Ratio) – 2016–2024 (%)

वर्ष	सरकारी बैंक	निजी बैंक
2016	42.5	38.2
2018	44.3	40.7
2020	45.7	42.9
2022	43.9	41.4
2024	42.0	40.1

CASA अनुपात बैंक की कम-लागत वाली धनराशि को दर्शाता है। तालिका से पता चलता है कि 2020 में दोनों श्रेणियों के बैंकों में CASA अनुपात अपने चरम पर था। इसका प्रमुख कारण महामारी के दौरान लोगों द्वारा अधिक बचत करना और डिजिटल बैंकिंग का तेजी से विस्तार था। 2022 और 2024 में मामूली गिरावट दिखती है, जिसका कारण बढ़ती महँगाई, उपभोक्ता खर्च में वृद्धि और वैकल्पिक निवेशों (FD, Mutual Funds) की ओर रुझान है। निजी बैंकों का CASA अनुपात सरकारी बैंकों से थोड़ा कम है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा नहीं है। CASA स्थिति स्थिर होने का अर्थ है कि बैंक अपनी फंडिंग लागत को संतुलित रूप से नियंत्रित कर पा रहे हैं।

तालिका 9: सेक्टर-वार ऋण वितरण – 2024 (₹ लाख करोड़)

क्षेत्र	ऋण वितरण
कृषि	15.2
उद्योग	32.5
MSME	21.8
आवास	19.4
सेवाएँ	28.6

2024 के सेक्टर-वार ऋण वितरण से स्पष्ट है कि उद्योग और सेवाएँ भारतीय ऋण बाजार के प्रमुख प्राप्तकर्ता हैं। उद्योग क्षेत्र को 32.5 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया गया, जो बड़ी परियोजनाओं, विनिर्माण और अवसंरचना विकास को दर्शाता है। वहीं MSME क्षेत्र को 21.8 लाख करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया, जो मुद्रा, CGTMSE और अन्य सरकारी योजनाओं के प्रभाव को मजबूत दिखाता है। कृषि क्षेत्र को दिया गया 15.2 लाख करोड़ रुपये का ऋण ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय वृद्धि को दर्शाता है। आवास ऋण में भी उल्लेखनीय वृद्धि से उपभोक्ता मांग बढ़ने का संकेत मिलता है।

तालिका 10 : बैंकों की लाभप्रदता – (%) – 2016–2024

वर्ष	सरकारी बैंक	निजी बैंक
2016	0.10	1.11
2018	-0.19	1.22
2020	0.32	1.38
2022	0.68	1.41
2024	0.85	1.49

तालिका दर्शाती है कि सरकारी बैंकों की लाभप्रदता 2016–2018 के दौरान NPA संकट के कारण प्रभावित हुई, जहाँ ROA नकारात्मक तक पहुँच गया। लेकिन 2019 के बाद IBC सुधार, पुनर्पूँजीकरण, और जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया मजबूत होने से सरकारी बैंकों का ROA लगातार बढ़ता गया और 2024 में 0.85% तक पहुँच गया। निजी बैंकों का प्रदर्शन पूरे अवधि में स्थिर और मजबूत रहा, जिनका ROA लगभग 1.1–1.5% के बीच रहा। निजी बैंक बेहतर प्रबंधन दक्षता, डिजिटल अवसंरचना और जोखिम नियंत्रण के कारण अधिक लाभप्रद बने हुए हैं। यह तालिका बैंकिंग क्षेत्र में स्थिरता और सुधार को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

तालिका 11 : वाणिज्यिक बैंकों के ब्याज दर रुझान – 2016–2024 (%)

वर्ष	जमा ब्याज दर (FD)	ऋण ब्याज दर
2016	7.3	10.5
2018	6.7	10.1
2020	5.6	9.0
2022	6.1	9.5
2024	6.8	10.2

तालिका दर्शाती है कि 2016–2020 के बीच ब्याज दरों में लगातार गिरावट हुई, जिसका कारण आर्थिक मंदी, कम मुद्रास्फीति और RBI की उदार मौद्रिक नीतियाँ थीं। 2020 में महामारी के समय ब्याज दरें ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर आ गईं। 2021–2024 में बढ़ती मांग, वैश्विक महँगाई और RBI की रेपो दर में वृद्धि के कारण दरें पुनः बढ़ने लगीं। ऋण ब्याज दरों में यह परिवर्तन सीधे उपभोक्ता ऋण, आवास ऋण और व्यवसायिक निवेश को प्रभावित करता है। बढ़ी हुई ब्याज दरें बैंकों की लाभप्रदता बढ़ाती हैं, लेकिन उधारी लागत भी बढ़ाती हैं।

तालिका 12 : डिजिटल बैंकिंग उपयोगकर्ता – 2016–2024 (करोड़)

वर्ष	इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता	मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ता
2016	12.5	9.4
2018	20.2	16.7
2020	34.8	29.3
2022	48.5	39.1
2024	61.2	52.7

Interpretation

तालिका बताती है कि भारत में डिजिटल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग दोनों में 2016–2024 के दौरान लगभग पाँच गुना वृद्धि देखी गई। इस वृद्धि के मुख्य कारण हैं – स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच में वृद्धि, UPI-आधारित भुगतान क्रांति, 4G नेटवर्क का विस्तार, और बैंकिंग सेवाओं का डिजिटल रूपांतरण। महामारी के दौरान लोगों ने ऑनलाइन लेनदेन को प्राथमिकता दी, जिससे उपयोगकर्ता संख्या और बढ़ी। यह ट्रेंड दर्शाता है कि भारत डिजिटल बैंकिंग की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है।

तालिका 13 : ATM उपलब्धता – 2016–2024 (संख्या में)

वर्ष	सार्वजनिक बैंक ATMs	निजी बैंक ATMs
2016	110,530	56,230
2018	112,890	61,400
2020	113,240	68,120
2022	114,900	71,350
2024	115,600	74,980

ATM नेटवर्क में वर्ष-दर-वर्ष स्थिर वृद्धि देखी गई है, विशेषकर निजी बैंकों द्वारा। सार्वजनिक क्षेत्र के ATMs की वृद्धि धीमी है, जबकि निजी बैंक तेजी से अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं। UPI और डिजिटल भुगतान के बढ़ने के कारण ATM उपयोग में कमी आई है, इसलिए बैंकों ने नए ATM लगाने की गति धीमी कर दी है। फिर भी, ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक बैंकों के ATM महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह संरचना दर्शाती है कि डिजिटल भुगतान के बावजूद नकद की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है।

तालिका 14 : विदेशी बैंकों की भारत में हिस्सेदारी – 2016–2024 (%)

वर्ष	क्रेडिट मार्केट शेयर	जमा मार्केट शेयर
2016	5.6	4.2
2018	5.3	4.0
2020	5.0	3.9
2022	4.8	3.7
2024	4.5	3.5

विदेशी बैंकों की भारत में बाजार हिस्सेदारी लगातार घट रही है। इसका कारण कठोर नियामक ढांचा, उच्च अनुपालन लागत, और निजी भारतीय बैंकों द्वारा तेज़ प्रतिस्पर्धा है। विदेशी बैंकों का फोकस मुख्यतः कॉर्पोरेट बैंकिंग, विदेशी मुद्रा सेवाओं और प्रीमियम ग्राहकों पर होता है। जमा और ऋण बाजार में उनकी हिस्सेदारी सीमित है, जो यह दर्शाता है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में घरेलू बैंकों का दबदबा अधिक है। यह प्रवृत्ति भारत के आत्मनिर्भर वित्तीय ढाँचे को भी दर्शाती है।

तालिका 15 : सीआरएआर/सीएआर (जोखिम भारित संपत्ति अनुपात के लिए पूंजी) - 2016-2024 (%)

वर्ष	सरकारी बैंक	निजी बैंक
2016	11.5	14.8
2018	10.9	15.1
2020	12.2	16.3

2022	14.5	17.2
2024	15.8	17.9

CRAR बैंकों की वित्तीय मजबूती का मुख्य संकेतक है। तालिका दर्शाती है कि सरकारी और निजी दोनों बैंकों का CRAR वर्षों में मजबूत हुआ है। सरकारी बैंकों का CRAR 2016–2018 में कमजोर था, जिसका कारण NPA संकट था। 2019–2024 के दौरान पुनर्पूँजीकरण, IBC सुधार, और बेहतर जोखिम प्रबंधन के कारण CRAR मजबूत हुआ। निजी बैंकों का CRAR लगातार ऊँचा रहा है, जो मजबूत पूँजी संरचना और कुशल संचालन का प्रतीक है। यह डेटा दर्शाता है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली वैश्विक मानकों के अनुरूप पूँजी-पर्याप्तता बनाए हुए है।

तालिका 16 : बैंकिंग क्षेत्र में निवेश रुझान – 2016–2024 (₹ लाख करोड़)

वर्ष	सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-Sec)	कॉर्पोरेट बॉन्ड	म्यूचुअल फंड निवेश
2016	22.3	6.1	1.9
2018	25.8	7.4	2.3
2020	30.2	9.6	3.1
2022	34.5	11.8	4.9
2024	37.8	13.4	6.2

इन्वेस्टमेंट पैटर्न स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में भारी निवेश करते हैं क्योंकि यह सुरक्षित और कम जोखिम वाला विकल्प है। 2016–2024 के बीच G-Sec में निरंतर वृद्धि सार्वजनिक बैंकों की सुरक्षा-प्रधान निवेश नीति को दर्शाती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी स्थिर वृद्धि हुई है, जिससे उद्योगों की पूँजी आवश्यकता को समर्थन मिलता है। म्यूचुअल फंडों में निवेश बढ़ना दर्शाता है कि बैंक अब विविधीकृत निवेश पोर्टफोलियो अपना रहे हैं। यह ट्रेंड बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता, जोखिम प्रबंधन और निवेश परामर्श की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

तालिका 17 : डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर – 2016–2024 (करोड़)

वर्ष	Aadhaar सत्यापन	e-KYC उपयोग	DBT लाभार्थी
2016	55.0	9.8	29.4
2018	88.4	22.3	37.2
2020	119.7	42.2	43.6
2022	138.5	58.6	49.8
2024	153.2	71.1	56.7

तालिका दर्शाती है कि डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को जड़ से परिवर्तित किया है। Aadhaar सत्यापन और e-KYC ने खाता खोलने की प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाया। DBT ने सरकारी लाभ सीधे बैंक खातों में पहुँचा कर पारदर्शिता बढ़ाई और लीकेज कम किया। डिजिटल पहचान और सत्यापन प्रणाली ने बैंकिंग पहुंच को गहरा किया और फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत बनाया। यह डेटा दर्शाता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर सिस्टम संचालित कर रहा है।

परिकल्पना परीक्षण

इस अध्ययन में भारतीय बैंकिंग प्रणाली, वाणिज्यिक बैंकों के प्रदर्शन, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA), तथा सरकारी योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु निम्न परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है। चूँकि अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों

पर आधारित है, इसलिए ट्रेंड विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण, और अनुपात विश्लेषण जैसे सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग किया गया।

परिकल्पना 1 (H1):

“वाणिज्यिक बैंकों में जमा (Deposits) में 2015–2024 के दौरान सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।”

परिकल्पना परीक्षण परिणाम

ट्रेंड विश्लेषण के आधार पर 2015 में कुल जमा 89.1 लाख करोड़ से बढ़कर 2024 में 189.5 लाख करोड़ हो गया। यह वृद्धि निरंतर, मजबूत और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाई गई।

निष्कर्ष: H1 स्वीकार (Accept)

व्याख्या: वित्तीय समावेशन योजनाओं, PMJDY, डिजिटल भुगतान और उपभोक्ता विश्वास में वृद्धि के कारण जमा में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है।

परिकल्पना 2 (H2):

“2016–2024 के बीच NPA अनुपात में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण कमी आई है।”

परिकल्पना परीक्षण परिणाम

NPA 2018 में 14.6% से घटकर 2024 में 6.2% हुआ। यह गिरावट निरंतर और अर्थपूर्ण है।

निष्कर्ष: H2 स्वीकार

व्याख्या: IBC कानून, बेहतर जोखिम प्रबंधन, ऋण पुनर्गठन और पारदर्शी क्रेडिट मूल्यांकन प्रणालियों के कारण NPA में उल्लेखनीय कमी आई है।

परिकल्पना 3 (H3):

“सरकारी योजनाओं (PMJDY, MUDRA) का बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय समावेशन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।”

परिकल्पना परीक्षण परिणाम

PMJDY खातों की संख्या 2015 के 18 करोड़ से बढ़कर 2024 में 51.1 करोड़ हो गई।

मुद्रा ऋण 2016 के 1.37 लाख करोड़ से बढ़कर 2024 में 5.23 लाख करोड़ पहुँच गया।

निष्कर्ष: H3 स्वीकार

व्याख्या: डेटा दर्शाता है कि सरकारी योजनाओं से बैंकिंग पहुँच में तीव्र विस्तार हुआ है।

परिकल्पना 4 (H4):

“निजी बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन (ROA/ROE) सार्वजनिक बैंकों की तुलना में सांख्यिकीय रूप से बेहतर है।”

परिकल्पना परीक्षण परिणाम

2016–2024 के सभी वर्षों में निजी बैंकों का ROA (1.1–1.5%) सार्वजनिक बैंकों (0.1–0.85%) से लगातार अधिक रहा।

निष्कर्ष: H4 स्वीकार

व्याख्या: तकनीकी श्रेष्ठता, कुशल प्रबंधन और कम NPA बोझ निजी बैंकों को बेहतर प्रदर्शन में सक्षम बनाता है।

परिकल्पना 5 (H5):

“डिजिटल बैंकिंग उपयोग (UPI, मोबाइल बैंकिंग) में वृद्धि से बैंकिंग दक्षता में सुधार हुआ है।”

परिकल्पना परीक्षण परिणाम

UPI उपयोग 2017 के 1.9 करोड़ से बढ़कर 2024 में 1102 करोड़ लेनदेन हो गया।

मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ता 2016 के 9.4 करोड़ से 2024 में 52.7 करोड़ तक पहुँच गए।

निष्कर्ष: H5 स्वीकार

व्याख्या: डिजिटल लेनदेन की वृद्धि ने लागत कम की, सेवा की गति बढ़ाई और दक्षता में सुधार किया।

परिकल्पना	स्थिति
H1: जमा में वृद्धि	स्वीकार
H2: NPA में कमी	स्वीकार
H3: योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव	स्वीकार
H4: निजी बैंक अधिक लाभप्रद	स्वीकार
H5: डिजिटल बैंकिंग ने दक्षता बढ़ाई	स्वीकार

परिकल्पना परीक्षण दर्शाता है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में पिछले दशक में संरचनात्मक सुधार, योजना कार्यान्वयन, डिजिटल प्रगति और जोखिम प्रबंधन उपायों के कारण उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

प्रमुख चुनौतियाँ

भारतीय बैंकिंग प्रणाली तेजी से विकसित हो रही है, लेकिन इसके सामने कई गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं। सबसे बड़ी समस्या गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की है, जिससे बैंकों की लाभप्रदता और ऋण क्षमता दोनों प्रभावित होती हैं। साइबर सुरक्षा खतरे और डिजिटल धोखाधड़ी डिजिटल बैंकिंग के विस्तार के साथ तेजी से बढ़ रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उच्च परिचालन लागत, तकनीकी पिछड़ापन और मानव संसाधन प्रबंधन की कमजोरियाँ अब भी चुनौतियाँ हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग जागरूकता की कमी, डिजिटल विभाजन तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में असमानता भी बाधाएँ उत्पन्न करती है। साथ ही, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और नियामकीय अनुपालन का बढ़ता दबाव बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित करता है।

सुझाव

भारतीय बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए बहु-स्तरीय सुधारों की आवश्यकता है। सबसे पहले, NPA प्रबंधन को तकनीक-आधारित करना चाहिए, ताकि ऋण निगरानी वास्तविक समय में हो सके। डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने हेतु साइबर सुरक्षा ढाँचा, डेटा एन्क्रिप्शन और ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम आवश्यक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मानव संसाधन प्रशिक्षण, प्रबंधन स्वायत्तता और प्रौद्योगिकी निवेश बढ़ाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता अभियान और बैंक मित्र को सुदृढ़ करना महत्वपूर्ण है। सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाए। निजी और सार्वजनिक बैंकों के बीच प्रतियोगिता बढ़ाने से सेवाओं की गुणवत्ता सुधर सकती है। अंततः, बैंकिंग क्षेत्र में नवाचार और फिनटेक सहयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है।

उपसंहार

भारतीय बैंकिंग प्रणाली का विकास एक गतिशील और बहुआयामी प्रक्रिया रहा है, जिसने देश की आर्थिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया है। प्राचीन महाजनी व्यवस्था से लेकर आधुनिक डिजिटल बैंकिंग तक, बैंकिंग प्रणाली ने समाज के हर वर्ग को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण, तकनीकी क्रांति, UPI और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे कदमों ने बैंकिंग को अधिक समावेशी, कुशल और पारदर्शी बनाया है। वाणिज्यिक बैंकों ने जमा संग्रह, ऋण वितरण, भुगतान प्रणाली और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से आर्थिक विकास को गति दी है। हालांकि बैंकिंग क्षेत्र के सामने NPA, डिजिटल सुरक्षा जोखिम, परिचालन अक्षमता, और नियामकीय दबाव जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। इन चुनौतियों के बावजूद भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने महत्वपूर्ण मजबूती हासिल की है, जिसका प्रमाण जमा और ऋण में निरंतर वृद्धि, NPA में कमी, डिजिटल लेनदेन में विश्व स्तर पर अग्रणी प्रदर्शन और वित्तीय समावेशन का विस्तार है। सही नीतियों, तकनीकी नवाचार, प्रभावी जोखिम प्रबंधन और मानव संसाधन विकास के माध्यम से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र भविष्य में और अधिक सक्षम, ग्राहक-केंद्रित और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बन सकता है। समग्र रूप से कहा जाए, तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली देश के आर्थिक विकास की रीढ़ है और आने वाले वर्षों में इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने वाली है।

संदर्भ सूची

1. शर्मा, आर. (2018). इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री और स्ट्रक्चर।
2. कुमार, एस. और सिंह, वी. (2020). इंडियन कमर्शियल बैंकों का परफॉर्मेंस।
3. मेहता, ए. (2019). इंडिया में NPA क्राइसिस: कारण और उपाय।
4. राव, जी. (2017). इंडिया में बैंक नेशनलाइजेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स।
5. वर्मा, पी. (2021). इंडिया में फाइनेंशियल इन्क्लूजन स्कीम्स।
6. अग्रवाल, टी. और थॉमस, एल. (2022). इंडिया में डिजिटल बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन।
7. चौधरी, एस. (2016). रूरल बैंकिंग और RRB परफॉर्मेंस।
8. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI). एनुअल रिपोर्ट्स (2015–2024).
9. RBI. इंडिया में बैंकों से जुड़े स्टैटिस्टिकल टेबल्स।
10. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया (अलग-अलग साल)।
11. NABARD. रूरल क्रेडिट रिपोर्ट का स्टेटस.
12. SIDBI. MSME सेक्टर रिपोर्ट.
13. PMJDY ऑफिशियल पोर्टल, भारत सरकार.
14. MUDRA योजना पोर्टल, भारत सरकार.
15. PM-SVANidhi स्कीम रिपोर्ट (2020–2024).
16. PM-किसान स्कीम डैशबोर्ड.
17. वर्ल्ड बैंक. ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट.
18. IMF. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू.
19. IBA (इंडियन बैंक्स एसोसिएशन) रिपोर्ट्स.

20. NPCI. UPI ट्रांजैक्शन स्टैटिस्टिक्स.
21. MoSPI. नेशनल स्टैटिस्टिकल डेटा.
22. EXIM बैंक इंडिया. एनुअल इकोनॉमिक रिव्यू.
23. NHB (नेशनल हाउसिंग बैंक) रिपोर्ट्स.
24. दास, एस. (2020). बैंकिंग सेक्टर पर डिजिटल पेमेंट्स का असर. 25. कपूर, आर. (2019). इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम – एक ओवरव्यू।
25. गुप्ता, एम. (2021). इंडिया में मॉडर्न बैंकिंग प्रैक्टिस।
26. जैन, ए. (2020). इकोनॉमिक ग्रोथ में कमर्शियल बैंकों की भूमिका।
27. सिंह, पी. (2018). इंडिया में बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स।
28. जोशी, एच. (2023). इंडियन बैंकिंग: चैलेंजेस और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स।
29. OECD. फाइनेंशियल इन्क्लूजन और डिजिटल इकोनॉमी पर रिपोर्ट्स।